



निगरानी प्र. क्रमांक / 2014  
प्रस्तुति दिनांक १७ अगस्त 2014

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, के समक्ष

R 3270 - PBR/14

1- रामू उर्फ रामलाल पिता राजाराम मृत तर्फे वारिस:-

अ- श्रीमती सीताबाई बेवा रामू उर्फ रामलाल मुकाती,  
आयु करीब 64 वर्ष, धंधा-गृहकार्य,  
निवासी खाती मोहल्ला, ग्राम मुसाखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.)  
हाल मुकाम ग्राम पानोड तहसील व ~~जिला इन्दौर (म.प्र.)~~

श्री. ओ.पी. झाय  
प्रार्थी/अभिधाषक द्वारा दिनांक 27/8/14

ब- मुकेश पिता रामू उर्फ रामलाल मुकाती,  
आयु करीब 44 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी सदर

प्रस्तुत  
547/27-08-2014

श्री. ओ.पी. झाय

स- रामप्रसाद पिता रामू उर्फ रामलाल मुकाती,  
आयु करीब 42 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी सदर

2- लक्ष्मीनारायण पिता राजाराम मुकाती,  
आयु करीब 66 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी सदर

3- शंकरलाल पिता राजाराम मुकाती,  
आयु करीब 60 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी सदर

4- गोविंद पिता राजाराम मुकाती,  
आयु करीब 58 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी सदर

--- प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश द्वारा :-  
नायब तहसीलदार, इन्दौर  
कार्यालय, कलेक्टोरेट कार्यालय,  
मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

2- नाथूजी पिता काशीराम खाती,  
निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग, तहसील सांवेर  
जिला इन्दौर (म.प्र.)

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज :- अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

कानून कार्यालय इन्दौर  
16/9/14

18.9.14

OPAS  
- 27/8/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3270-पीबीआर / 14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-5-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25.6.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर मौरुषी कृषक के आधार पर नामांतरण चाहा गया है । संहिता की धारा 110 के अंतर्गत बने नियमों में संशोधन के फलस्वरूप नवीन नियमों में केवल हक के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त नामांतरण नियम 32 के अंतर्गत भी केवल हक के आधार पर ही नामांतरण किये जाने का प्रावधान है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा मौरुषी कृषक के आधार पर किये नामांतरण को कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः कलेक्टर की आदेश पुष्टि कर निगरानी निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	